



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 134]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 16, 2008/श्रावण 25, 1930

No. 134]

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 16, 2008/SRAVANA 25, 1930

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 12 अगस्त, 2008

सं. टीएएमपी/22/2006-टीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 और 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार, बिजली की आपूर्ति के मामले में उपरिख्य प्रभार वसूल करने के लिए लेवी के निर्धारण हेतु तृतीकोरिन पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव का निपटान करता है।

अनुसूची

मायला सं. टीएएमपी/22/2006-टीपीटी

तृतीकोरिन पत्तन न्यास

—आवेदक

आदेश

(जुलाई, 2008 के 14वें दिन पारित)

यह मामला बिजली की आपूर्ति के मामले में उपरिख्य प्रभार वसूल करने के लिए लेवी निर्धारण हेतु तृतीकोरिन पत्तन न्यास (टीपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित मामला है।

21. तृतीयकोरिन पत्तन न्यास (टीपीटी) ने बिजली आपूर्ति के मामले में उपरिख्य प्रभारों के 20 प्रतिशत निर्धारण हेतु नवम्बर, 2003 में पहले एक प्रस्ताव दाखिल किया था।

22. तथापि, इस प्राधिकरण ने टीपीटी के प्रस्ताव पर विचार दो मुख्य कारणों से टाल दिया था। प्रथमतः उपरिख्य की दो बार गिनती की जानी थी एक बार सामान्य प्रशुल्क और प्रस्ताव लेवी के द्वारा दोबारा परिकलन। दूसरा, निजी टर्मिनल प्रचालक पीएसए एसआईसीएल से उपरिख्य प्रभारों की वसूली जैसे कुछ विधिक मुद्दे और विनियामकों के न्यायाधिकार थे जिन्हें प्रस्तावित प्रशुल्क अनुमोदित करने से पहले देखे जाने थे। टीपीटी को तमिल नाडु बिजली विनियामक आयोग (टीएनईआरसी) के समक्ष इस मुद्दे को रखने और इस मामले में सही विधिक स्थिति पर उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने की सलाह दी गई थी। यह भी स्पष्ट नहीं था कि टीएनईबी की अनुसूचित दर' शब्दावली प्रस्तावित उपरिख्य लेवी में शामिल की जाएगी अथवा नहीं।

अतः टीपीटी को आदेश सं. टीएमपी/79/2003-टीपीटी दिनांक 4 मई, 2004 द्वारा सलाह दी गई थी कि लेवी का प्रस्ताव अपने दरमान के सामान्य संशोधन के भाग के रूप में करे परंतु विभिन्न विधिक मुद्दों पर स्पष्टीकरण देने होंगे।

3.1. इस परिप्रेक्ष्य में, टीपीटी ने भौजूदा प्रस्ताव दाखिल किया है। प्रस्ताव में, टीपीटी द्वारा कही गई मुख्य बातें निम्नलिखित हैं—

(i). टीएनईबी द्वारा आपूर्ति बिजली निम्नलिखित द्वारा उपभोग की जाती है।

(क) पत्तन साइड: सरकारी भवन, सविदाकार/पत्तन उपयोक्ता, क्वार्टर्स, शॉपिंग सेंटर, घाट क्रैन।

(ख) पीएसए एसआईसीएल टर्मिनल्स लिमिटेड (पीएसए एसआईसीएल)

(ii). टीएनईबी द्वारा माँगा गया हाई टेंशन बिल पूरी तरह से टीपीटी द्वारा भुगतान किया जाता है। तथापि, पीएसए एसआईसीएल के मामले में, एक पृथक ट्रांसफार्मर प्रणाली संस्थापित की गई है। पीएसए एसआईसीएल द्वारा उपभोग की गई बिजली के लिए प्रभार टीएनईबी द्वारा निर्धारित प्रशुल्क के आधार पर टीपीटी द्वारा वसूल किए जाते हैं। इसके अलावा, पीएसए एसआईसीएल से अधिकतम माँग प्रभार और मीटर किराया प्रभार भी वसूल किए जाते हैं।

(iii). टीपीटी ने पत्तन उपयोक्ताओं और पीएसए एसआईसीएल के बीच बिजली के वितरण की लागत दर्शाते हुए वर्ष 2003-04 से 2008-09 के लिए लागत पत्रक भेजे थे। वर्ष 2003-04 से 2008-09 के लिए पत्तन उपयोक्ताओं/सविदाकारों तथा पीएसए एसआईसीएल से प्रत्यक्ष निर्धारित लागत की वसूली के लिए टीपीटी द्वारा भेजे गए लागत विवरणों का सार नीचे तालिकाबद्ध किया गया है—

1. पत्तन साइड (सविदाकार/पत्तन उपयोक्ता)

क्र. सं.	विवरण	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1.	उपभोग की गई इकाईयें	2577041	2311308	2860642	2860642	2860642	2860642
2.	बिजली प्रभार (अधिकतम माँग प्रभार अतिरिक्त)	14321659	12450055	14620920	16117789	16676919	17252823
3.	अधिकतम माँग प्रभार	2084275	1312291	1678245	1665905	1665905	1665905
4.	आवृत्ति बिजली विभाग प्रभार	3812600	3175794	4131576	4450586	4584104	4721627
5.	वसूल की जाने वाली कुल राशि (3+4)	5896875	4488085	5809821	6116491	6250009	6387532
6.	% मूल बिजली प्रभार (5/2)	41.19%	35.99%	39.73%	38.01%	37.39%	36.98%
7.	औसत %			38%			

## 2. पीएसए एसआईसीएल टर्मिनल्स लिमिटेड

क्र. सं.	विवरण	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1.	उपभोग की गई इकाईयाँ	2278688	2315129	2971809	2971809	2971809	2971809
2.	बिजली प्रभार	12633590	12470635	15189102	16744141	17324999	17923283
3.	अवॉल्ट बिजली विभाग प्रभार	3371202	3181043	4292133	4623540	4762246	4905114
4.	% मूल बिजली प्रभार (3/2)	26.62%	25.42%	28.18%	27.71%	27.44%	27.36%
5.	औसत %	27%					

(iv). टीपीटी द्वारा भेजे गए लागत पत्रक में अवॉल्ट प्रबंधन और सामान्य उपरिचय, पेंशन भुगतान, नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ आदि शामिल हैं। चूंकि ये अप्रत्यक्ष लागत तत्व महत्वपूर्ण हैं, इसलिए टीपीटी ने उपभोग की गई बिजली की लागत पर केवल 20 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष निर्धारित लागत (अर्थात् बिजली विभाग बिल और अधिकतम मॉग प्रभार) वसूल करने का प्रस्ताव किया है।

(v). पीएसए एसआईसीएल के मामले में, चूंकि अधिकतम मॉग प्रभार अलग-से वसूल किए जाते हैं, इसलिए लेवी की गणना में अधिकतम मॉग प्रभार शामिल नहीं किया गया है। पीएसए एसआईसीएल के मामले में भी, टीपीटी का प्रस्ताव विभागीय व्ययों की औसत पूर्ति के लिए पीएसए एसआईसीएल द्वारा उपभोग की गई बिजली के लिए बिजली लागत का 20 प्रतिशत वसूल करने के लिए है। बचाया व्यय इसके पतन प्रभुत्व के सामान्य संशोधन प्रस्ताव के हिस्से के रूप में प्रबंधन और सामान्य उपरिचय तथा प्रतिलाभ के साथ आमेतिट किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

3.2. टीपीटी ने 30 अप्रैल, 2006 को हुई अपनी बैठक में प्रस्तावित दर अनुमोदित करते हुए बोर्ड संकल्प की प्रतिलिपि अंग्रेषित की थी।

3.3. टीपीटी ने अपने प्रस्ताव के साथ दिनांक 18 जून, 2004 को तमिल नाडु बिजली विनियामक आयोग (टीएनईआरसी) द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए हैं। टीएनईआरसी ने सूचित किया है कि हाई टेंशन (एचटी) आपूर्ति के लिए निर्धारित प्रभुत्व आयोग द्वारा निर्धारित से भिन्न नहीं हो सकता है और टीएनईआरसी केवल प्रभुत्व से संबद्ध है और सभी अन्य प्रभार टीएनईआरसी के न्यायाधिकार में नहीं आता है।

3.4. टीपीटी ने तमिल नाडु बिजली बोर्ड (टीएनईबी) का पत्र दिनांक 8 जुलाई, 2004 भी अंग्रेषित किया है। टीएनईबी ने सूचित किया है कि ट्रांसफार्मर नुकसान, अधिकतम मॉग प्रभारों, आदि के रूप में अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए पट्टाधारकों (बिजली के उपयोक्ता) से पतन उपरिचय प्रभारों की वसूली करता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। अभी तक उपरिचय प्रभार बोर्ड के निबंधन एवं शर्तों के 31.03 (1) के उपबंधों का विधिवत् अनुपालन करते हुए वसूल किए जाते हैं बशर्ते वसूली 'न लाभ न हानि' पर की जाए। इसके बाद, टीएनईबी ने यह भी सूचित किया था कि चूंकि टीपीटी टीएनईबी का उपयोक्ता है ना कि लाइसेंसधारी, इसलिए उपरिचय प्रभारों की वसूली करने के लिए टीएनईआरसी का अनुमोदन अपेक्षित नहीं है।

3.5. यह मुद्दा कि क्या प्रस्तावित लेवी लाइसेंस करार के खंड 6.1.8 के मद्देनजर पीएसए एसआईसीएल पर लागू की जा सकती है जिसमें विनिर्दिष्ट किया जाता है कि लाइसेंसधारी पर प्रभार प्रभार टीएनईबी की अनुसूचित दर के अनुसार होगा, तथापि प्रस्ताव में स्पष्ट नहीं किया गया है।

4.1. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, टीपीटी का प्रस्ताव पीएसए एसआईसीएल और संबद्ध उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों को उनकी टिप्पणियों के लिए अंग्रेषित किया गया था।

4.2. उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों से प्राप्त टिप्पणियाँ टीपीटी को प्रतिपुष्टि सूचना के रूप में अंग्रेषित की गई थीं। टीपीटी ने उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों की टिप्पणियों पर अपना प्रतिसाद भेजा था।

5. प्रस्ताव की प्राथमिक जाँच के आधार पर, टीपीटी से विभिन्न बिन्दुओं पर अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण भेजने के लिए अनुरोध किया गया था। टीपीटी ने प्रतिसाद में हमारे प्रश्नों पर अपने जवाब भेजे थे। हमारे द्वारा उठाए गए प्रश्नों और टीपीटी द्वारा भेजे गए जवाब का सार नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

क्र.सं.	हमारे द्वारा उठाए गए प्रश्न	टीपीटी द्वारा भेजे गए जवाब
(i).	बिजली लागत वितरण का विवरण सामान्य संशोधन प्रस्ताव में दिए गए अनुमानों के तदनुसारी वर्ष 2009-10 के अनुमानों के साथ अधुनातन करें।	बिजली लागत वितरण का विवरण सामान्य संशोधन प्रस्ताव में दिए गए अनुमानों के साथ तदनुसारी वर्ष 2009-10 तक अधुनातन किया गया है। संशोधित विवरण के अनुसार, प्रत्यक्ष निर्धारित लागत की वसूली के लिए वर्ष 2007-08 से 2008-10 के वास्तविक और अनुमानों के आधार पर वर्ष 2004-05 से 2006-07 के लिए औसत उपरिचय दर पत्तन साइड उपयोक्ताओं (संविदाकारों/पत्तन उपयोक्ताओं) के मामले में बिजली लागत का 43.18 प्रतिशत और पीएसए एसआईसीएल के मामले में 31.82 प्रतिशत परिणामित होती है।
(ii).	कृपया स्पष्ट करें कि गार्ड/डॉक, पत्तन प्रशासनिक कार्यालय भवन, पत्तन अस्पताल, सड़कों का कार्यालय, भंडारण क्षेत्र आदि में अपने प्रचालनों के लिए पत्तन द्वारा बिजली का उपयोग इस विवरण में कैसे सुविचारित किए गए हैं। यदि सुविचारित नहीं किया जाता है तो यह विवरण इन लेखों पर पत्तन द्वारा बिजली के उपयोग के साथ अधुनातित किया जाए और उपरिचय प्रभारों को भी समान अनुपात में आबंटित किया जाए।	प्रशासनिक भवनों, अस्पताल, स्ट्रीट लाइट, आदि में मौजूदा उपयोग की जाँच करने के लिए ऊर्जा मीटर संस्थापित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। तथापि, सरकारी भवनों, संविदाकारों/पत्तन उपयोक्ताओं, क्वार्टरों, शॉपिंग सेंटर और घाट क्रेनों का समूहीकरण उपरिचय के प्रभाजन के मुद्दे पर विचार करता है।
(iii).	यह प्रस्ताव संविदाकारों/पत्तन उपयोक्ताओं और पीएसए एसआईसीएल से उपरिचय प्रभारों की वसूली करने के लिए है। इस लेवी को उपयोक्ताओं की अन्य श्रेणियों जैसे शॉपिंग सेंटरों के किरायेदार, अन्य सरकारी भवन और पत्तन तथा उन स्थानों जहाँ पत्तन द्वारा निशुल्क बिजली उपलब्ध करवाई जाती है, से इतर उपयोक्ताओं के लिए प्रस्तावित नहीं करने के कारण स्पष्ट करें।	संविदाकारों/पत्तन उपयोक्ताओं से इतर पक्षों के मामले में उपरिचय प्रभार सामान्य संशोधन प्रस्ताव में प्रासंगिक लागत जोड़ते हुए वसूल किए जाएंगे, क्योंकि अन्य उपयोक्ताओं की प्रमुखता धुकनें आदि है जोकि पत्तन कॉलोनी में रहने वाले पत्तन कर्मचारियों के लिए सुविधा है।
(iv).	गुष्टि करें कि वर्ष 2003-04 से 2005-06 के लिए विवरण में निर्दिष्ट बिजली प्रभार और उपरिचय प्रभार वास्तविक हैं। वर्ष 2006-07 से 2008-09 के लिए बिजली प्रभारों के अनुमान का आधार स्पष्ट करें। अनुमानों का विस्तृत ब्रेकअप प्रत्येक वर्ष के लिए भेजा जाए।	वर्ष 2003-04 से 2005-06 के विवरण में निर्दिष्ट बिजली प्रभार और उपरिचय प्रभार वास्तविक हैं। वर्ष 2006-07 के लिए संशोधित अनुमान (आर.ई.) और वर्ष 2007-08 के लिए बजट अनुमान (बी.ई.) अनुमानित किए गए हैं। अनुवर्ती वर्षों के लिए, 2007-08 के लिए बजट अनुमान में 3 प्रतिशत वृद्धि सुविचारित की गई है।
(v).	विभिन्न उपयोक्ताओं अर्थात् सरकारी भवन, संविदाकारों, पत्तन उपयोक्ताओं, शॉपिंग सेंटरों, पीएसए एसआईसीएल आदि के बीच बिजली विभाग में किए गए उपरिचय के आबंटन का आधार स्पष्ट करें।	विभिन्न उपयोक्ताओं अर्थात् सरकारी भवन, संविदाकारों, पत्तन उपयोक्ताओं, शॉपिंग सेंटरों, पीएसए एसआईसीएल आदि के बीच बिजली विभाग में किया गया उपरिचय तत्संबंधी श्रेणियों द्वारा उपयोग की गई इकाईयों की संख्या के आधार पर प्रमाणित की गई है।
(vi).	पीएसए एसआईसीएल के मामले में अधिकतम माँग प्रभार वर्ष 2006-06 से विशेष रूप से बढ़े हैं और सभी अन्य उपयोक्ताओं के मामले में पत्तन साइड के लिए अधिकतम माँग प्रभार अनुमानों से अधिक पाए गए हैं। इसके कारण स्पष्ट करें।	(क). पीएसए एसआईसीएल ने 1200 सवीए की अधिकतम माँग (एमडी) के लिए गॉंग की थी परंतु वर्ष 2006-07 के दौरान वास्तव में मापी गई अधिकतम माँग लगभग केवल 800 कवीए आई थी। बीओटी करार के खंड B.1.8 के अनुसार, बिजली की आपूर्ति के लिए, पत्तन द्वारा पीएसए एसआईसीएल पर प्रभार टीएनईबी की अधिसूचित दरों के अनुसार है। (ख). हाई ट्रांसमिशन (एचटी) प्रमुख के लिए टीएनईबी के अनुसार, अधिकतम माँग मंजूरीसुदा अधिकतम माँग अथवा अभिलेखित अधिकतम माँग, जो भी अधिक हो, के 90 प्रतिशत पर वसूल की जाएगी। इसलिए, 1200 कवीए का 90 प्रतिशत, जोकि 1080 कवीए है, वसूल करता है, यह प्रकृति में स्थिर है और इसमें बढ़ोतरी नहीं देखी गई है।

(vii).	यह पाया गया है कि प्रस्तावित लेवी अधिकतम मांग प्रभार और पीएसए एसआईसीएल से इतर संविदाकारों/पत्तन उपयोक्ताओं से बिजली विभाग प्रभारों को वसूल करने के लिए है। इसके विपरीत, पत्र दिनांक 28 अगस्त, 2006 द्वारा भेजे गए विस्तृत परिकलन पत्रक में निर्दिष्ट किया गया है कि एचटी उपभोक्ता से वसूल की गई रू० 6.20 प्रति इकाई अधिकतम मांग प्रभारों में पहले से शामिल है। पुष्टि करें कि इस लेवी के माध्यम से अधिकतम मांग प्रभारों की वसूली में कोई दोहरीकरण नहीं हुआ है और यह स्थिति भी स्थापित करें जोकि लागत विवरण में विनिर्दिष्ट है।	पीएसए एसआईसीएल के मामले में बिजली उपरिचय प्रभारों की गणना में अधिकतम मांग प्रभारों की राशि शामिल नहीं की गई है और केवल बिजली विभाग प्रभार का व्यय शामिल किया गया है। इसलिए, इस लेवी के माध्यम से अधिकतम मांग प्रभारों की वसूली में दोहरीकरण नहीं है।
(viii).	30 अप्रैल, 2006 को हुई टीपीटी के न्यासी बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त निर्दिष्ट करते हैं कि बिजली उपरिचय प्रभारों के रूप में 50 पैसे प्रति इकाई की अधिक वसूली के बारे में किसी न्यासी द्वारा कही गई बात की जांच करने के लिए सहमत था। इस संबंध में पत्तन द्वारा की गई समीक्षा का परिणाम बताएं।	30 अप्रैल, 2006 को हुई टीपीटी के न्यासी बोर्ड की बैठक में यथा सहमत, विभिन्न उपयोक्ताओं के लिए मौजूदा उपभोग प्रभारों और दावा की समीक्षा की गई है और पाया गया कि लिपिकीय गलती के कारण किसी एक उपभोक्ता अर्थात् मै० सी पोर्ट लोजिस्टिक्स से अधिक प्रभार वसूल किए गए हैं और बाद में मौजूदा उपभोग प्रभार में अधिक राशि को समायोजित करते हुए इसका अनुसमर्थन किया गया है।
(ix).	पीएसए एसआईसीएल के साथ हस्ताक्षरित बीओटी करार का खंड 6.1.8 विनिर्दिष्ट करता है कि लाइसेंसधारी पर प्रभार्य टीएनईबी की दरों की अनुसूची के अनुसार होंगे। टीपीटी द्वारा पहले प्राप्त की गई विधिक राय भी इस स्थिति का समर्थन करती है। बीओटी करार में विशिष्ट खंड और टीपीटी द्वारा पहले मांगी गई विधिक राय के मद्देनजर, कृपया पुष्टि करें कि क्या पीएसए एसआईसीएल टर्मिनल लि० से बिजली के वितरण के लिए उपरिचय प्रभारों की वसूली करने के लिए टीपीटी लाइसेंस करार (एलए) के अधीन अधिकृत है।	(क). बीओटी करार के खंड 6.1.8 के अनुसार, बिजली और जल आपूर्ति संबंधी, पत्तन द्वारा पीएसए एसआईसीएल पर प्रभार्य प्रभार टीएनईबी द्वारा दरों की अनुसूची के अनुसार होने चाहिए। लाइसेंसधारी से उपरिचय प्रभारों की वसूली करने के लिए अनुमोदन हेतु टीएनईबी का रुख करते समय, यह सल्लेख किया गया है कि ट्रांसफार्मर नुकसान, अधिकतम मांग प्रभारों, आदि के रूप में अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए लाइसेंसधारी से उपरिचय प्रभारों की वसूली करने में टीएनईबी को कोई आपत्ति नहीं है, अभी तक उपरिचय प्रभार टीएनईबी की निष्पत्ति एवं शर्तों के उपबंध 31.03 (1) का विधिवत अनुपालन करते हुए वसूल किए जाते हैं अर्थात् वसूली 'न लाभ न हानि आधार' पर की जाती है। (ख). जब तमिल नाडु बिजली विनियामक आयोग (टीएनईआरसी) का रुख किया गया, वह बताया गया कि टीपीटी एचटी आपूर्ति के अधीन उपयोक्ताओं/लाइसेंसधारियों पर प्रशुल्क दरें आयोग द्वारा निर्धारित प्रशुल्क से भिन्न नहीं हो सकती है। टीएनईआरसी केवल प्रभार्य प्रशुल्क दरों से संबद्ध है और कोई अन्य प्रभार उनके न्यायाधिकार में नहीं आता है। (ग). यह प्रस्ताव 'न लाभ न हानि आधार' पर बिजली उपरिचय प्रभारों की वसूली के लिए है और बिजली उपरिचय प्रभारों की वसूली के लिए टीएनईआरसी को कोई आपत्ति नहीं है।
(x).	टीपीटी द्वारा हाल ही में दायित्व सामान्य संशोधन प्रस्ताव में शामिल नहीं किए गए बिजली उपरिचय से संबंधित व्यय मौजूदा प्रस्ताव में सुविचारित उपरिचय से मेल नहीं खाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए इन आंकड़ों को संशोधित करें कि सामान्य संशोधन प्रस्ताव में शामिल नहीं किए गए बिजली उपरिचय मौजूदा प्रस्ताव में वसूल किए जाने के लिए प्रस्तावित उपरिचय से मेल खाए।	सामान्य संशोधन प्रस्ताव में शामिल नहीं किए बिजली उपरिचय संबंधी व्यय प्रस्तावित लेवी द्वारा वसूल किए जाने के लिए प्रस्तावित वसूली को दर्शाने के लिए संशोधित किया गया है।

8. इस मामले में संयुक्त सुनवाई 13 जुलाई, 2007 को तृतीकोरिन पत्तन न्यास परिसर में आयोजित की गई थी। संयुक्त सुनवाई में, टीपीटी और संबद्ध उपयोक्ताओं ने अपने निवेदन प्रस्तुत किए थे।

7.1. संयुक्त सुनवाई में उपयोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदनों से यह लगता है कि सही तरीके से उपरिचय्य वसूली बढ़ेगी यदि और जब तमिल नाडु बिजली बोर्ड अपने प्रशुल्क में ऊर्ध्वमुखी संशोधन करता है। इसलिए, टीपीटी से स्थिति की बारीकी से जाँच करने और इसका स्पष्टीकरण भेजने की सलाह दी गई थी। टीपीटी को यह सलाह भी दी गई थी कि वह प्रासंगिक बीओटी करार के संदर्भ में पीएसए एसआईसीएल टर्मिनल्स लिमिटेड द्वारा उठाई गई आपत्ति का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करें और इस संबंध में विस्तृत नोट भेजें।

7.2. संयुक्त सुनवाई में की गई चर्चा के प्रतिसाद में, टीपीटी ने निम्नलिखित बातें रखी थीं।

- (i). तमिल नाडु बिजली बोर्ड (टीएनईबी) द्वारा बिजली प्रशुल्क में वृद्धि से उपरिचय्य वसूली में वृद्धि संबंधी बिन्दु प्रकट होता है क्योंकि उपरिचय्य वसूली की दर उपयोग की गई इकाईयों पर बिल किए गए मूल बिजली प्रभारों पर प्रस्तावित की गई है। न्याय करने के लिए इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित (किए जाने वाले) प्रशुल्क के मामले में टीएनईबी द्वारा घोषित प्रशुल्क में वृद्धि/घटाव के अनुपात में अधोमुखी अथवा ऊर्ध्वमुखी प्रतिशत को पुनः निर्धारित करने के लिए पत्तन सहमत है। इसने प्राधिकरण से, इस संबंध में, प्रशुल्क आदेश में उपयुक्त टिप्पणी शामिल करने का अनुरोध किया है।
- (ii). पीएसए एसआईसीएल से उपरिचय्य वसूल करने के प्रस्ताव के बारे में दूसरे बिन्दु के संबंध में, इसने पीएसए एसआईसीएल की टिप्पणियों पर इसके पूर्ववर्ती निवेदनों और इस संबंध में इस प्राधिकरण द्वारा उठाए गए प्रश्न पर इसके जवाब का उल्लेख किया था। इसने बाद में निवेदन किया था कि पीएसए एसआईसीएल के मामले में बिजली पर उपरिचय्य प्रभारों की लेवी के इसके प्रस्ताव पर इस प्राधिकरण द्वारा अंतिम निर्णय तबित रखते हुए अधिशेष/घाटा स्थिति का अनुमान लगाने के लिए अपने दरमान के सामान्य संशोधन के लिए तैयार किए गए संशोधित लागत विवरण में संबंधित व्यय शामिल किया गया है।

8. इस मामले में विचार-विमर्श संबंधी कार्यवाहियाँ इस प्राधिकरण के कार्यालय में अभिलेखों में उपलब्ध हैं। प्राप्त हुई टिप्पणियों और संबद्ध पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों का सार प्रासंगिक पक्षों को अलग-से भेजा जाएगा। ये ब्योरे हमारी वेबसाइट <http://nariffauthority.gov.in> पर भी उपलब्ध होंगे।

9. इस मामले की कार्यवाही के दौरान एकत्र की गई समग्र सूचना के संदर्भ में, निम्नलिखित स्थिति विचार के लिए प्रकट होती है।

- (i). तृतीकोरिन पत्तन न्याय (टीपीटी) का प्रस्ताव बिजली के वितरण में पत्तन द्वारा किए गए प्रत्यक्ष व्यय का हिस्सा वसूल करने के लिए एक नई प्रशुल्क मद शामिल किए जाने के लिए है।

टीपीटी तमिल नाडु बिजली बोर्ड (टीएनईबी) से थोक में बिजली प्राप्त करता है और अपने क्षेत्र के भीतर वितरण की व्यवस्था करता है। पत्तन प्रासंगिक उपयोक्ता के उपयोग प्रारूप के आधार पर आधारित लागू दरों पर टीएनईबी को भुगतान किया जा रहा प्रशुल्क अपने उपयोक्ताओं से वसूल करता है। टीएनईबी को देय बिजली प्रभारों के अलावा, पत्तन अपने क्षेत्र के भीतर बिजली के वितरण के लिए अपेक्षित अवसंरचना व्यवस्थित करता है और उनपर व्यय करता है। मौजूदा व्यवस्था में, संबंधित उपरिचय्य व्यय सामान्य प्रशासनिक उपकरणों के हिस्से के रूप में माने जाते हैं और विभिन्न गतिविधियों में प्रभाजित किए जाते हैं। पत्तन का प्रस्ताव प्रत्यक्ष व्ययों जोकि प्रासंगिक उपयोक्ताओं से अपने प्रस्ताव में उपरिचय्य प्रभारों के रूप में उल्लिखित हैं, के हिस्से के रूप में वसूल करने के लिए है।

इस प्राधिकरण ने टीपीटी द्वारा इस संबंध में पहले वर्ष 2003 में दस्तखत प्रस्ताव का सैद्धांतिक रूप से समर्थन किया था। जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है, टीपीटी के पूर्ववर्ती प्रस्ताव पर विचार कुछ विधिक मुद्दों पर पत्तन से स्पष्टीकरण माँगे जाने और प्रस्तावित लेवी द्वारा के साथ-साथ पत्तन के सामान्य प्रशुल्क में वसूल किए जाने के लिए प्रस्तावित लागत तत्वों की दोहरी गणना के बारे में शंका उत्पन्न होने के कारण टाला गया था।

- (ii). पिछले आदेश में उठाए गए मुख्य बिन्दुओं को मौजूदा प्रस्ताव में टीपीटी द्वारा संशोधित किया गया है। पत्तन ने बताया है कि ट्रांसफार्मर नुकसान, अधिकतम मांग प्रभारों आदि के रूप में अतिरिक्त व्ययों को पूरा करने के लिए लाइसेंसधारियों से उपरिचय्य प्रभारों की पत्तन द्वारा वसूली करने पर तमिल नाडु बिजली बोर्ड ने कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की है, बशर्त वसूली टीएनईबी द्वारा बिजली की आपूर्ति के लिए निबंधन और शर्तों के खंड 31.03 (1) के अनुपालन में न लाभ न हानि आधार पर की जाती है। टीपीटी ने पुष्टि की है कि इसका प्रस्ताव टीएनईबी द्वारा निर्धारित उक्त शर्त का अनुपालन करता है।

विनियामक न्यायाधिकार के मुद्दे पर, तमिल नाडु बिजली विनियामक आयोग (टीएनईआरसी) ने टीपीटी को सूचित किया था कि आयोग केवल प्रशुल्क और अन्य प्रभारों से संबंध है और अन्य प्रभार आयोग के न्यायाधिकार के अधीन नहीं आते हैं।

यह प्राधिकरण टीपीटी द्वारा आवश्यक दस्तावेज़ी समर्थन के साथ किए गए निवेदनों पर विश्वास करता है। यह उल्लेखनीय है कि समान प्रशुल्क व्यवस्था प्रासंगिक लाइसेंसधारियों/अभिधारकों से बिजली के वितरण के लिए पत्तन को उपरिष्ठ प्रमारों की वसूली में समर्थ बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के दरमान में उपलब्ध है।

टीपीटी ने बिजली उपरिष्ठों के रूप में परिभाषित व्यय मदों, जिन्हें नई लेवी के माध्यम से वसूल करने के लिए प्रस्तावित किया गया है, को लागत तत्वों के दोहराकरण को दूर करने के लिए अपने दरमान के सामान्य संशोधन के लागत विवरण से अलग रखा है।

- (iii). यह प्रस्ताव टीएनईडी को भुगतान किए जाने वाले मूल प्रमारों से ऊपर प्रत्यक्ष लागत का हिस्सा वसूल करने की अनुमति के लिए है। जैसाकि पत्तन द्वारा पुष्टि की गई है, इसने प्रस्तावित लेवी से कोई लाभ कमाने का प्रस्ताव नहीं किया है। यह प्रस्ताव पत्तन की गतिविधियों पर प्रासंगिक व्यय का बोझ डालने की बजाय इसे सामान्य व्यय के रूप में शामिल करते हुए संबद्ध उपयोक्ताओं से व्यय की प्रत्यक्ष वसूली करने के लिए है।

यद्यपि लागत तत्व जैसे प्रबंधन और सामान्य उपरिष्ठ, पेंशन भुगतान, नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ, आदि पत्तन द्वारा तैयार किए गए लागत पत्रक में शामिल किए गए हैं, परंतु वे लेवी प्रतिशत के परिकलन के लिए सुविचारित नहीं किए जाते हैं। वे घटक पत्तन द्वारा दाखिल सामान्य संशोधन प्रस्ताव में प्रासंगिक लागत मदों के हिस्से के रूप में बनाए रखा गया है। अतः कुछ लागत तत्वों की दोहरी गणना और परिकलन में लाभ तत्व को प्रभावित करने के बारे में कुछ उपयोक्ता असंतुष्टियों द्वारा अभिव्यक्त आशंका नहीं पाई गई है।

- (iv). पत्तन द्वारा आपूर्ति बिजली के उपयोक्ताओं को वृद्धतः सरकारी भवन, संविदाकारों, पत्तन उपयोक्ताओं, कर्मचारी क्वार्टरों, शॉपिंग सेंटरों, घाट क्रेन और पीएसए एसआईसीएल टर्मिनल्स लिमिटेड में समूहित किया गया है।

पत्तन ने टिप्पणी की है कि अलग रखी गई श्रेणी पत्तन कॉलोनी में रहने वाले पत्तन कर्मचारियों की जरूरत को अधिकतम पूरा करती है और, इसलिए, उपयोक्ताओं की इन श्रेणियों पर आबंटनीय भाग को सामान्य व्ययों के रूप में माना गया है और सामान्य पत्तन प्रशुल्क पर डाला गया है।

पत्तन द्वारा बताया गया कारण स्वीकार्य प्रतीत नहीं होता है। अलग रखी गई श्रेणियों का बोझ भी उपयोक्ताओं की अन्य श्रेणियों पर स्थानांतरित नहीं किया गया है चूंकि प्रत्यक्ष उपरिष्ठ का केवल एक भाग प्रस्तावित लेवी के माध्यम से वसूल किया जाता है, इसलिए प्रस्तावित व्यवस्था तर्कसंगत प्रतीत नहीं होगी। अतः टीपीटी को उपर्युक्त कमी के आलोक में मामले की जांच करने और अगली प्रशुल्क समीक्षा के समय उपयुक्त संशोधन करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है।

- (v). जून, 2007 में भेजे गए संशोधित लागत विवरण में, वर्ष 2006-07 से संबंधित आंकड़े वास्तविक से अधुनातित किए गए हैं और पूर्व अवधि वर्ष 2004-05 और 2005-06 के लिए उपयोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों पर व्यय का आबंटन भी संशोधित किया गया है।

बिजली का उपयोग प्रतिरूप अनुवर्ती दो वर्षों 2008-09 और 2009-10 के लिए वर्ष 2007-08 के स्तर पर माना गया है। वर्ष 2007-08 के लिए बिजली विभाग के व्यय वर्ष 2007-08 के बजट अनुमानों पर आधारित अनुमानित बताए गए हैं। अनुवर्ती दो वर्षों के लिए, 3 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि तत्संबंधी पिछले वर्षों के अनुमानों पर व्ययों के अनुमानन में सुविचारित की गई है। वार्षिक वृद्धि 4.6 प्रतिशत जो वर्ष 2008-09 में निर्णीत प्रशुल्क मामलों के लिए सुविचारित की जा सकती है। व्ययों के अनुमानन के लिए वार्षिक वृद्धि स्वीकार्य वृद्धि के भीतर पाई जाएगी। टीपीटी द्वारा संशोधित लागत विवरण में दिए गए लागत अनुमानों के साथ-साथ उपयोग प्रतिरूप पर लेवी के निर्धारण के लिए विश्वास किया गया है।

- (vi). वर्ष 2008-09 और 2009-10 के लिए औसत प्रत्यक्ष लागत उपयोक्ताओं और संविदाकारों द्वारा उपयोग की गई बिजली की औसत इकाई लागत का 38.42 प्रतिशत है। इसके विपरीत, पत्तन का प्रस्ताव बिजली लागत के 20 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष लागत वसूल करने के लिए है, जोकि अनुमोदित किया जाता है।

- (vii). बिजली विभाग से संबंधित व्यय और अधिकतम मांग प्रभार सामान्यतः सामान्य स्थिति झुकाव जोकि लेवी के परिकलन में पहले से लागू है, के कारण विभागीय व्ययों में कुछ सीमांतक वृद्धि के लिए, प्रकृति में निर्धारित किए जाते हैं।

प्रासंगिक उपयोक्ता द्वारा उपयोग की गई बिजली की औसत लागत के प्रतिशत रूप में लेवी वसूल करने के लिए टीपीटी का प्रस्ताव टीएनईडी द्वारा घोषित बिजली की दर की इकाई में तदनुकूली वृद्धि पूरी अवधि में वसूल किया जा सकता है।

टीपीटी समुक्त सुनवाई में टीएनईबी द्वारा घोषित प्रशुल्क में बदलाव के अनुपात में लेवी में अधोमुखी अथवा ऊर्ध्वमुखी पुनः निर्धारित करने के लिए सहमत था। यह अधिक उपयुक्त है कि राही तरीके से लेवी निर्धारित की जाए ताकि संबद्ध उपयोक्ताओं द्वारा देय प्रशुल्क में स्थिरता हो। इसलिए, वर्ष 2006-07 के लिए पत्तन उपयोक्ताओं/संविदाकारों द्वारा भुगतान किए गए बिजली प्रभारों की वस्तुस्थिति औसत इकाई दर पर लेवी की प्रस्तावित प्रतिशतता लागू करते हुए लेवी निर्धारित की गई है।

संविदाकारों/पत्तन उपयोक्ताओं से वसूल बिजली प्रभारों की औसत इकाई दर, अधिकतम मांग प्रभार अतिरिक्त, वर्ष 2006-07 के लिए रु० 5.70 प्रतिवेदित की गई है। अतः लेवी प्रासंगिक उपयोक्ता द्वारा उपभोग की गई बिजली की रु० 1.15 प्रति इकाई निर्धारित की जाती है।

- (viii). टीपीटी ने पीएसए एसआईसीएल को बिजली की आपूर्ति को भी प्रस्तावित लेवी की परिधि के भीतर लाने का प्रस्ताव किया है। पीएसए एसआईसीएल ने यह दावा करते हुए प्रस्तावित लेवी को चुनौती दी है कि उसे बीओटी करार के अनुसार टीएनईबी की अधिसूचित दरों पर आधारित प्रभारों की प्रतिपूर्ति करनी होगी।

बीओटी करार का खंड 6.1.8 बिजली और जल आपूर्ति व्यवस्था को विनियमित करता है। प्रासंगिक खंड स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करता है कि लाइसेंसधारी पर प्रभार प्रभार टीएनईबी की अनुसूचित दर के अनुसार होगा। टीपीटी द्वारा पहले प्राप्त की गई विधिक राय भी पीएसए एसआईसीएल द्वारा व्यवस्थित स्थिति का समर्थन करती है।

तथापि, टीपीटी ने टीएनईबी के पत्र का उल्लेख किया है जिसमें टीपीटी द्वारा ट्रांसफार्मर नुकसान, अधिकतम मांग प्रभारों, आदि के रूप में अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए पट्टाधारक से उपरिव्यय प्रभारों की वसूली करने पर अनापत्ति स्प्रेषित की थी, अभी तक उपरिव्यय प्रभार टीएनईबी की निबंधन और शर्तों के 31.03 (1) के उपबंधों का विधिवत् पालन करते हुए वसूल किए जाते हैं, अर्थात् वसूली न लाभ न हानि आधार पर की जाती है। टीएनईबी द्वारा दिया गया स्थानीयकरण सामान्यतः टीपीटी को उपरिव्यय प्रभारों की वसूली की अनुमति प्रदान करता है परंतु बीओटी करार में शामिल उपबंध की जाँच करने के पश्चात् पीएसए एसआईसीएल के विशिष्ट मामले में दिया गया प्रतीत नहीं होता है।

टीपीटी स्पष्ट रूप से यह पुष्टि करने में असमर्थ रहा है कि वह पीएसए एसआईसीएल से बिजली के वितरण हेतु उपरिव्यय वसूल करने के लिए बीओटी करार के अधीन अधिकृत है। अतः पीएसए एसआईसीएल से उपरिव्यय प्रभारों की लेवी के लिए टीपीटी का प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया गया है।

संयोगवश, टीपीटी ने भी बाद में पीएसए एसआईसीएल के मामले में बिजली पर उपरिव्यय प्रभारों की लेवी के अपने प्रस्ताव पर इस प्राधिकरण द्वारा अंतिम निर्णय लंबित रखते हुए अपने दरमान के सामान्य संशोधन के लिए तैयार किए गए संशोधित लागत विवरण में अधिशेष/घाटा स्थिति का अनुमान लगाने के लिए पीएसए एसआईसीएल से संबंधित व्यय को शामिल किया है।

- (ix). इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरें भारत के राजपत्र में आदेश की अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों के पश्चात् लागू होती हैं। जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है, लागत तत्वों के दोहरीकरण को रोकना सुनिश्चित करने के लिए पत्तन प्रशुल्क के सामान्य संशोधन के साथ इस मामले को समान रूप से अंतिम रूप दिया गया है। अतः यह आदेश सामान्य संशोधन मामले में अनुमोदित टीपीटी के संशोधित दरमान के कार्यान्वयन की तारीख से आदेश को लागू होगा। पत्तन उपयोक्ताओं/संविदाकारों से उपरिव्ययों की वसूली के लिए लेवी टीपीटी के संशोधित दरमान में शामिल की गई है।

इस विश्लेषण में सुविचारित लागत स्थिति दो वर्षों अर्थात् 2008-09 और 2009-10 के लिए है। इसके बाद, यह उपयुक्त होगा कि इस प्रशुल्क मद की समीक्षा इसके दरमान में निर्धारित अन्य प्रशुल्क मदों की समीक्षा के साथ की जाए। ऐसी स्थिति में, बिजली के वितरण के लिए उपरिव्यय वसूल करने के लिए लेवी की वैधता इसके संशोधित दरमान के साथ को-टर्मिनस बनाने के लिए 31 मार्च, 2010 तक निर्धारित की गई है।

10. परिणामस्वरूप, और उपर्युक्त कारणों से, और समग्र विचार-विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण पत्तन उपयोक्ताओं/संविदाकारों से बिजली की आपूर्ति के लिए उपरिव्यय व्यय वसूल करने के लिए उपभोग की गई बिजली की रु० 1.15 प्रति इकाई की लेवी अनुमोदित करता है।

ब्रह्म दत्त, अध्यक्ष

[ विज्ञापन III/4/143/08-असा. ]



## TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

## NOTIFICATION

Mumbai, the 12th August, 2006

No. TAMP/22/2006-TPT.—In exercise of the powers conferred by Sections 48 and 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes the proposal received from the Tuticorin Port Trust for fixation of levy to recover overhead charges in respect of supply of Electricity as in the Order appended hereto.

## SCHEDULE

Case No. TAMP/22/2006-TPT

Tuticorin Port Trust

—Applicant

## ORDER

(Passed on this 14th day of July 2008)

This case relates to a proposal received from Tuticorin Port Trust (TPT) for fixing levy to recover overhead charges in respect of supply of electricity.

2.1. The Tuticorin Port Trust (TPT) had earlier filed a proposal in November 2003 for fixing 20% of electricity charges towards recovery of overhead charges in respect of electricity supply.

2.2. This Authority had, however, deferred consideration of the proposal of the TPT on two main reasons. Firstly, the overheads appeared to be counted twice once in the general tariff computation and again by way of the proposed levy. Secondly, there were some legal issues like recovering the overhead charges from the private terminal operator PSA SICAL and the jurisdictions of regulators, which needed to be frontally addressed before approving the proposed tariff. The TPT was advised to refer the issue to the Tamil Nadu Electricity Regulatory Commission (TNERC) and obtain their guidance on the correct legal position in this matter. It was also not clear whether the term 'scheduled rate of TNEB' would include the proposed overhead levy.

The TPT was, therefore, advised vide Order No. TAMP/79/2003-TPT dated 4 May 2004 to propose the levy as part of the general revision of its Scale of Rates subject to clarifications on the various legal issues.

3.1. In this backdrop, the TPT has filed the instant proposal. The main points made by the TPT in the proposal are as follows:

- (i). The electricity supplied by the TNEB is consumed by the following:
  - (a) Port side: Government Buildings,  
Contractors / Port users,  
Quarters,  
Shopping center,  
Wharf crane.
  - (b) PSA SICAL Terminals Limited (PSA SICAL)
- (ii). The High Tension bill raised by TNEB is wholly paid by the TPT. In the case of PSA SICAL, however, a separate transformer system is installed. The charges for electricity consumed by PSA SICAL are collected by the TPT on the basis of the tariff prescribed by the TNEB. Apart from that, maximum demand charges and meter rent charges are also collected from the PSA SICAL.
- (iii). The TPT has furnished cost sheets for the years 2003-04 to 2008-09 showing the cost of distribution of electricity amongst the port users and the PSA SICAL. A summary of the cost statements furnished by the TPT for recovery of direct fixed cost from the port users / contractors and PSA SICAL for the years 2003-04 to 2008-09 is tabulated below:

## 1. Port Side (Contractors / Port Users)

Sl. No.	Particulars	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1.	Units consumed	2577041	2311308	2860642	2860642	2860642	2860642
2.	Electricity Charges (excluding maximum Demand charges)	14321659	12450055	14620920	16117769	16576919	17252823

3	Maximum Demand Charges	2084275	1312291	1678245	1665905	1665905	1665905
4	Allocated Electrical Dept Charges	3812600	3175794	4131576	4450586	4584104	4721627
5	Total Amount to be recovered (3+4)	5896875	4488085	5809821	6116491	6250009	6387532
6	% to the basic electricity charges (5 / 2)	41.19%	35.98%	39.73%	38.01%	37.39%	36.98%
7	Average %				38%		

## 2. PSA SICAL Terminals Limited

Sl. No.	Particulars	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1.	Units consumed	2278688	2315129	2971809	2971809	2971809	2971809
2.	Electricity Charges	12633590	12470635	15189102	16744141	17324999	17923283
3	Allocated Electrical Dept Charges	3371202	3181043	4292133	4623540	4762246	4905114
4	% to the basic electricity charges (3/ 2)	26.62%	25.42%	28.18%	27.71%	27.44%	27.36%
5.	Average %				27%		

(iv). The cost sheet furnished by the TPT include allocated management and general overheads, pension payments, return on capital employed, etc., Since these indirect cost elements are significant, the TPT proposes to recover the direct fixed cost (i.e. electricity department charges and maximum demand charges) only to the extent of 20% on the cost of electricity consumed.

(v). In case of PSA SICAL, since maximum demand charges are collected separately, the computation of levy excludes maximum demand charges. In case of PSA SICAL as well, the proposal of the TPT is to recover 20% of the electricity cost for the power consumed by PSA SICAL to partly meet the departmental expenses. The balance expenditure is proposed to be absorbed along with the management and general overheads and return as part of its general revision proposal of port tariff.

3.2. The TPT has forwarded a copy of the Board Resolution approving the proposed rate in its meeting held on 30 April 2006.

3.3. The TPT has alongwith its proposal submitted the clarification issued by Tamil Nadu Electricity Regulatory Commission (TNERC) dated 18 June 2004. The TNERC has informed that the tariff fixed for the High Tension (HT) supply cannot be different from that fixed by the Commission and the TNERC is concerned with the tariff only and that all other charges do not fall under the jurisdiction of the TNERC.

3.4. The TPT has also forwarded the communication of the Tamil Nadu Electricity Board (TNEB) dated 9 July 2004. The TNEB has informed that it has no objection in the port collecting the overhead charges from the lessees (i.e. users of the electricity) to meet the additional expenditure in terms of transformer loss, Maximum Demand charges, etc., insofar as the overhead charges are collected duly complying with provisions of 31.03 (1) of the Terms and Conditions of Board provided the collection is made on "no profit no loss basis". Further, the TNEB has also informed that since the TPT is a consumer of the TNEB and not a licensee, approval of the TNERC is not required for collecting the overhead charges.

3.5. The issue whether the proposed levy can be applied on PSA SICAL in view of Clause 6.1.8 of the License Agreement which specifies that charges levied on the licensee shall be as per the 'scheduled rate of the TNEB' is, however, not made clear in the proposal.

4.1 In accordance with the consultative procedure prescribed, the proposal of TPT was forwarded to the PSA SICAL and concerned users / user organisations seeking their comments.

4.2 The comments received from the users/user organisations were forwarded to TPT as feedback information. The TPT has furnished its response to the comments of the users / user organisations.

5. Based on a preliminary scrutiny of the proposal, the TPT was requested to furnish additional information/clarifications on the various points. The TPT in response has furnished its reply to our queries. A summary of the queries raised by us and reply furnished by TPT is tabulated below:

Sl. No.	Queries raised by us	Reply furnished by TPT
(i).	The statement of electricity cost distribution may be updated with the estimates for the year 2009-10 corresponding with the estimates furnished in the general revision proposal.	The statement of electricity cost distribution has been updated upto 2009-10 corresponding with the estimates furnished in the general revision proposal. As per the revised statement, the average overhead rate for the years 2004-05 to 2006-07 based on actuals and estimates for 2007-08 to 2009-10 for recovery of direct fixed cost works out to be 43.18% of electricity cost in respect of port side users (Contractors/Port users) and 31.82% in case of PSA SICAL.
(ii).	Clarify how the consumption of electricity by the port for its operations at the yard/ dock, port administrative office building, port hospitals, illumination of the roads, storage area etc., are considered in this statement. If not considered, then the statement may be updated with the consumption of electricity by the port on these accounts and the overhead charges may also be allocated proportionately.	Action is being taken to install energy meter to assess the current consumption at administrative buildings, hospital, street light, etc. The groupings of Government Buildings, Contractors/Port Users, Quarters, Shopping center and wharf cranes, however, consider the issue of apportionment of overhead.
(iii).	The proposal is for levying overhead charges from the contractors / port users and the PSA SICAL. Explain the reasons for not proposing this levy on the other categories of users like tenants of the shopping centres, other government buildings, and users other than the port and at places where the port is obliged to provide free electricity.	The overhead charges in respect of parties other than contractors/ports users will be recovered by clubbing the relevant cost in the general revision proposal, as the majority of other users are shops etc., meant for port employees residing at port colony.
(iv).	Confirm that the electricity charges and the overhead charges indicated in the statement for the years 2003-04 to 2005-06 are at actuals. Explain the basis of estimating the electricity charges for the years 2006-07 to 2008-09. A detailed breakup of the estimates may be furnished for each of the years.	The electricity charges and the overhead charges indicated in the statement for the years 2003-04 to 2005-06 are at actuals. For the year 2006-07, Revised Estimates (R.E.) and for the year 2007-08 Budget Estimates (B.E.) are considered. For the subsequent years, 3% increase has been considered on B.E.2007-08.
(v).	Explain the basis of allocation of the overhead incurred in the electricity department between the various users, i.e. government building, contractors, port users, shopping centres, PSA SICAL, etc.	The overhead incurred in the electricity department between the various users, i.e., government building, contractors, port users, shopping centers, PSA SICAL etc., is apportioned based on number of units consumed by the respective categories.
(vi).	The maximum demand charges in case of the PSA SICAL increases significantly from the year 2006-06 onwards and is found to be higher than the maximum demand charges estimates for port side in respect of all the other users. The reasons therefor may be explained.	(a) PSA SICAL has demanded for 1200 KVA of Maximum Demand (MD) but the actually measured MD comes to around only 800 KVA during 2006-07. As per clause 8.1.8 of the BOT agreement, for the supply of power, the charges must be levied on PSA SICAL by port as per the scheduled rates of TNEB.

		(b). As per TNEB for High Transmission (HT) tariff, the maximum demand will be charged at 90% of sanctioned MD or the recorded MD whichever is higher. Therefore, the port is charged for 90% of 1200 KVA, which is 1080 KVA, the same is constant in nature and it is not seen increasing
(vii).	It is found that the levy proposed is to recover the maximum demand charges plus electrical department charges from contractors / port users other than the PSA SICAL. As against this, detailed calculation sheet furnished vide letter dated 28 August 2006 indicate that Rs. 6.20 per unit collected from the HT consumer is already inclusive of the maximum demand charges. Confirm that there is no duplication in collection of maximum demand charges by way of this levy and also establish this position is reflected in the cost statement.	In the calculation of electricity overhead charges in respect of PSA SICAL, the amount of maximum demand charges has been excluded and only the expenditure of electrical department charges is included. Hence, there is no duplication in collection of maximum demand charges by way of this levy.
(viii).	The minutes of the meeting of the Board of Trustees of the TPT held on 30 April 2006 show that it was agreed to examine the point made by one of the Trustees about excess collection of 50 paise per unit as electricity overhead charges. Intimate the outcome of the review conducted by the port in this regard	As agreed in the Board of Trustees of TPT meeting held on 30 April 2006, the current consumption charges and claim for various users has been reviewed and found that excess charges has been collected from one of the user viz. M/s Sea Port Logistics due to clerical mistake and the same has been rectified by adjusting the excess amount in subsequent current consumption charge.
(ix).	Clause 6.1.8. of the BOT Agreement signed with the PSA SICAL specify that charges levied on the licensee shall be as per the schedule of rates of the TNEB. The legal opinion obtained by TPT earlier also endorses this position. In view of the specific clause in the BOT Agreement and legal opinion sought by the TPT earlier, please confirm whether the TPT is authorised under the License Agreement (LA) to recover overhead charges for distribution of electricity from the PSA SICAL Terminals Ltd.	<p>(a). As per clause 6.1.8. of the BOT Agreement, relating to power and water supply, the charges levied on PSA SICAL by port should be as per the schedule of rates by TNEB. While approaching the TNEB for the approval for collecting overhead charges from the lessee, it is stated that TNEB has no objection in collecting overhead charges, from the lessee to meet additional expenditure in terms of transformer loss, MD charges, etc., insofar as the overhead charges are collected duly complying with the provisions of 31.03 (1) of the Terms and Conditions of the TNEB i.e., collection is made on 'no profit no loss basis'.</p> <p>(b). When approached, the Tamil Nadu Electricity Regulatory Commission (TNERC), it has stated that the tariff rates to the users/lessees under TPT HT supply cannot be different from the tariff fixed by the Commission. The TNERC are concerned only with the tariff rates chargeable and any other charges do not fall under their jurisdiction.</p> <p>(c). The proposal is for collection of electricity overhead charges on 'no profit no loss basis' and there is no objection from TNERC for the recovery of electricity overhead charges.</p>
(x).	The expenditure relating to the electricity overheads excluded in the general revision proposal filed recently by the TPT do not match with the overheads considered in the instant	The expenditure relating to the electricity overheads excluded in the general revision proposal is modified to reflect the recovery proposed to be collected by the proposed levy.

proposal. Modify these figures to ensure that the electricity overheads excluded from the general revision proposal tallies with the overhead proposed to be recovered in the instant proposal.	
---	--

6. A joint hearing in this case was held on 13 July 2007 at the Tuticorin Port Trust premises. At the joint hearing, the TPT and the concerned users made their submissions.

7.1. The submissions made by the users at the joint hearing gave an impression that the overhead recovery in absolute terms would increase if and when the Tamil Nadu Electricity Board revises its tariff upwards. The TPT was, therefore, advised to examine the position closely and furnish its explanation. The TPT was also advised to carefully analyse the objection raised by PSA SICAL Terminals Limited with reference to the relevant BOT agreement and furnish a detailed note in this regard.

7.2. In response to the decisions taken at the joint hearing, the TPT has submitted the following points:

- (i). The point about increase in overhead recovery with increase in the electricity tariff by the Tamil Nadu Electricity Board (TNEB) arises because the rate of overhead recovery is proposed on the basic electricity charges billed on units consumed. In order to do justice, the port agrees to re-fix the percentage downwards or upwards in proportion to the increase / decrease in the tariff announced by the TNEB with respect to the tariff fixed by the Authority. It has requested the Authority to incorporate a suitable note in this regard in the tariff Order.
- (ii). As regards the second point about proposal to recover overhead from PSA SICAL, it has referred to its earlier submissions made on the comments of PSA SICAL and its reply to the query raised by the Authority in this regard. It has further submitted that the related expenditure has been included in the revised cost statement prepared for general revision of its Scale of Rates for estimating the surplus / deficit position pending a final decision by the Authority on its proposal to levy overhead charges on electricity in respect of PSA SICAL.

8. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the comments received and arguments made by the concerned parties will be sent separately to the relevant parties. These details is also be made available at our website <http://tariffauthority.gov.in>

9. With reference to the totality of the information collected during the processing of this case, the following position emerges:

- (i). The proposal of the Tuticorin Port Trust (TPT) is for introduction of a new tariff item to recover part of the direct expenses incurred by the port in distribution of electricity.

The TPT procures in bulk electricity from the Tamil Nadu Electricity Board (TNEB) and arranges distribution within its area. The port recovers from its users the tariff being paid to the TNEB at the applicable rates based on the consumption pattern of the relevant user. In addition to the electricity charges payable to the TNEB, the port maintains the required infrastructure for distribution of electricity within its area and incurs expenditure on them. In the existing arrangement the related overhead expenses are treated as part of the general administrative overheads and apportioned to the various activities. The proposal of the port is to recover part of the direct expenses which is referred as overhead charges in its proposal from the relevant users.

This Authority had in principle endorsed the proposal filed by the TPT earlier in 2003 in this regard. As already mentioned, the consideration of the earlier

proposal of the TPT was deferred for want of clarification from the port on certain legal issues and on account of a doubt arising about double counting of the cost elements proposed to be recovered in the general tariff of the port as well as by the proposed levy.

- (ii). The main issues raised in the last Order are addressed by the TPT in the instant proposal. The port has reported that the Tamil Nadu Electricity Board have expressed no objection to the port collecting the overhead charges from the lessees to meet the additional expenses in terms of transformer loss, Maximum Demand charges etc, provided the collection is made on no profit no loss basis in compliance with the clause 31.03 (1) of the terms and conditions for supply of electricity by the TNEB. The TPT has confirmed that its proposal complies with the said condition set by the TNEB.

On the issue of regulatory jurisdiction, the Tamil Nadu Electricity Regulatory Commission (TNERC) has informed the TPT that the Commission is only concerned with the tariff and other charges do not fall under the jurisdiction of the Commission.

This Authority relies on the submissions made by the TPT with necessary documentary support. It is noteworthy that a similar tariff arrangement is available in the Scale of Rates of the Jawaharlal Nehru Port Trust to enable the port to recover the overhead charges for distribution of electricity from the relevant lessees / occupants.

The TPT has excluded the expenditure items termed as electricity overheads which are proposed to be recovered by way of the new levy from the cost statements for the general revision of its Scale of Rates to eliminate overlapping of the cost elements.

- (iii). The proposal seeks to recover part of the direct cost incurred over and above the basic charges paid to the TNEB. As confirmed by the port, it does not propose to make any profit out of the proposed levy. The proposal is to recover part of the direct expense from the concerned users instead of loading the relevant expenditure to the activities of the port by including it as general expense.

Though the cost elements like management and general overheads, pension payments, return on capital employed, etc. are included in the cost sheet drawn by the port, they are not considered for computation of levy percentage. These components continue to be a part of the relevant cost items in the general revision proposal filed by the port. Therefore, the apprehension expressed by some of the user associations about double counting of certain cost elements and factoring a profit element in the computation is found to be misplaced.

- (iv). The consumers of electricity supplied by the port broadly are grouped into Government building, contractors, port users, employee quarters, shopping centers, wharf crane and PSA SICAL Terminals Limited.

The port has argued that the excluded category predominately caters to the need of the port employees residing at port colony and, therefore, the portion allocable to these categories of users is treated as general expenses and loaded on to the general port tariff.

The reason adduced by the port does not appear to be convincing. Even though the burden of the excluded categories is not transferred to the other categories of users since only a part of direct overhead is recovered through the proposal levy, the proposed arrangement does not appear to be logical. The TPT is, therefore, advised to examine the matter in the light of the above observation and propose a suitable modification at the time of next tariff review.

- (v). In the revised cost statement furnished in June 2007, the figure pertaining to 2006-07 are updated with actuals and allocation of expenses to the various categories of users for the past period 2004-05 and 2005-06 has also been modified.

The consumption pattern of the electricity is assumed to be at the level of 2007-08 for the subsequent two years 2008-09 and 2009-10. The expenses of electricity department for the year 2007-08 is reportedly estimated based on the Budget Estimates 2007-08. For the subsequent two years, an annual increase of 3% is considered in estimation of the expenses over the estimates of the respective previous years. The annual escalation that can be considered for the tariff cases decided in 2008-09 is 4.6%. The annual increase considered by the TPT for estimation of the expenses is found to be within admissible escalation. The cost estimates as well as consumption pattern furnished by the TPT in the revised cost statement are relied upon for fixing the levy.

- (vi). The average direct cost for the years 2008-09 and 2009-10 is 38.42% of the average unit cost of electricity consumed by the port users and contractors. As against this, the proposal of the port is to recover the direct cost to the extent of 20% of the electricity cost, which is approved.
- (vii). The expenses pertaining to the electrical department and the maximum demand charges are generally fixed in nature except for some marginal increase in the departmental expenses due to normal inflationary trend, which is already factored in the computation of levy.

The proposal of the TPT to recover the levy as a percentage of the average cost of electricity consumed by the relevant user may result in the levy in absolute terms to increase with corresponding increase in the unit of rate of power, if announced by the TNEB.

The TPT at the joint hearing agreed to re-fix the levy downwards or upwards in proportion to the change in the tariff announced by the TNEB. It is more appropriate to prescribe the levy in absolute terms so that there is certainty in the tariff payable by the concerned users. The levy is, therefore, fixed applying the proposed percentage of levy on the actual average unit rate of the electricity charges paid by the port users / contractors for the year 2008-07.

The average unit rate of the electricity charges collected from the contractors / port users excluding maximum demand charges is reported at Rs. 5.70 for the year 2008-07. The levy is, therefore, fixed at Rs. 1.15 per unit of power consumed by the relevant user.

- (viii). The TPT has proposed to bring the supply of electricity to PSA SICAL also within the ambit of the proposed levy. The PSA SICAL has challenged the proposed levy claiming that it has to reimburse charges based on the scheduled rates of TNEB as per the BOT Agreement.

Clause 6.1.8. of the BOT agreement regulates power and water supply arrangement. The relevant clause clearly specifies that the charges levied on the licensee shall be as per the scheduled rate of the TNEB. The legal opinion obtained by TPT earlier also endorses the position maintained by PSA SICAL.

The TPT has, however, referred TNEB's communication which conveyed no objection to TPT collecting overhead charges, from the lessee to meet additional expenditure in terms of transformer loss, MD charges, etc., insofar as the overhead charges are collected duly complying with the provisions of 31.03 (1) of the Terms and Conditions of the TNEB i.e., collection is made on 'no profit no loss basis'. The clarification given by the TNEB generally permits TPT to levy

overhead charges but it does not appear to have been given in the specific case of PSA SICAL after examining the provisions contained in the BOT Agreement.

The TPT has not been able to explicitly confirm that it is authorised under the BOT Agreement to recover the overhead for distribution of electricity from the PSASICAL. The proposal of the TPT to levy overhead charges from PSA SICAL is, therefore, not approved.

Incidentally, even the TPT has subsequently included the related expenditure pertaining to the PSA SCAL for estimating the surplus / deficit position in the revised cost statement prepared for general revision of its Scale of Rates pending a final decision by this Authority on its proposal to levy overhead charges on electricity in respect of PSA SICAL.

- (ix). The rates approved by this Authority are to be implemented after 30 days from the date of notification of the Order in the Gazette of India. As already mentioned earlier, this case has been finalised simultaneously with the general revision of the port tariff to ensure there is no overlapping of the cost elements. The Order is, therefore, to be given effect from the date of implementation of the revised Scale of Rates of the TPT approved in the general revision case. The levy for recovery of overheads from the port users / contractors is incorporated in the revised Scale of Rates of the TPT.

The cost position considered in this analysis is for two years i.e. 2008-09 and 2009-10. Further, it may be appropriate to review this tariff item along with the review of other tariff items prescribed in its Scale of Rates. That being so, the validity of the levy to recover the overhead for distribution of electricity is prescribed till 31 March 2010 to make it co-terminus with the validity of its revised Scale of Rates.

10 In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority approves levy of Rs. 1.15 per unit of electricity consumed to recover overhead expenses for supply of electricity from port users/ contractors

BRAHM DUTT, Chairman

[ADVT III/4/143/08-Exty.]